

भारत में नोटबंदी का बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव : एक अध्ययन

डॉ मनिंदर कौर

असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यापार प्रशासन, वाणिज्य विभाग, आर. बी. एस. कॉलेज, आगरा

शोधसारांश – भारत सरकार की विमुद्रीकरण नीति से हर कोई वाकिफ है, जिसमें 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसका प्रभाव नकदी में व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायों आदि पर तात्कालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा परन्तु इसके दूरगामी परिणाम अच्छे हुए, इससे टैक्स देनदारियों में बढ़ोतरी हुई और तमाम लोगों का काला धन बाहर निकला और बड़े पैमाने पर बैंकों में जमा हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लेन-देन नकद में किया जाता है, इसलिए वहां के व्यवसायों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। हालांकि विमुद्रीकरण ने तरलता को प्रभावित किया, यह मुद्रास्फीति, काले धन, भ्रष्टाचार और अपराध से निपटने, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को रोकने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अल्पकालिक अच्छा उपकरण था। विमुद्रीकरण का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। बैंकिंग उद्योग पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक सभी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैध मुद्रा वाले धन के वितरण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। यह व्यवसाय विमुद्रीकरण के मुख्य स्रोत है। विमुद्रीकरण ने बैंकों को शुल्क वसूल किए बिना भुगतान लेने के लिए मजबूर किया और बैंकों की तरलता की स्थिति में काफी सुधार किया। विमुद्रीकरण के बाद उपलब्ध साहित्य का उपयोग वर्तमान पेपर के विश्लेषण तैयार करने के लिए किया गया था। इसमें दिखाया गया है कि कैसे विमुद्रीकरण ने बैंकिंग उद्योग को प्रभावित किया। इसमें विमुद्रीकरण के साथ-साथ भारतीय वित्तीय उद्योग पर इसके प्रगतिशील प्रभाव के संबंध में केंद्र सरकार के सबसे हालिया निर्णय को शामिल किया गया है।

मुख्य शब्द : विमुद्रीकरण, बैंकिंग उद्योग, भुगतान, काला धन, भ्रष्टाचार आदि।

बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा होते हैं। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के सुचारू कामकाज के लिए धन का उपयोग किया जाता है। ग्रीन बैंकिंग की पहल ने बैंकों को पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं को आधुनिक बैंकिंग सेवाओं में बदलने के लिए तैयार किया। उत्पादों और सेवाओं को इंटरनेट की मदद से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पेश किया जाता है। अब बैंक सेवाओं को ग्राहकों की उंगली के इशारे पर पूरा किया जाता है। काले धन पर 'विमुद्रीकरण' नामक सर्जिकल स्ट्राइक ने देश के सभी क्षेत्रों में भारी परिवर्तन ला दिया। बैंक विमुद्रीकरण के प्रभाव से अपवाद नहीं हैं।

और इसने परिचालनों के साथ—साथ बैंकों के उत्पादों और सेवाओं में भी कंपन कैपिटल बैंकिंग सेवाओं की अधिक मांग पैदा की जहां कैशलेस लेनदेन को प्राथमिकता दी जाती है। इससे बैंकों के दिन—प्रतिदिन के संचालन प्रभावित होते हैं। इससे बैंकों में तरलता और कर्मचारियों के प्रबंधन में कठनाई आई। इसने जोखिम को कम करते हुए और सेवा की गुणवत्ता को अधिकतम करते हुए अपने प्रतिबंधित मुद्रा नोटों के आदान—प्रदान में ग्राहकों द्वारा उठाई गई तरलता के प्रबंधन और इसकी मांग पर अधिक प्रभाव डाला, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। विमुद्रीकरण ने बैंक संचालन को अस्त—व्यस्त कर दिया और कर्मचारियों को दिन के विस्तारित कार्य घंटों में बिना शर्त तनाव में काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। अधिकांश बैंक प्रतिबंधित मुद्रा नोटों को बदलने के दौरान अन्य बैंकिंग सेवाओं का निर्वहन करने में सक्षम नहीं थे। वर्तमान अध्ययन बैंकिंग क्षेत्र पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया है। यह बैंकों और उसके परिचालनों पर विमुद्रीकरण के बाद के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

वर्तमान परिदृश्य

आज सभी बैंकों और एटीएम की एक स्पष्ट तस्वीर मौजूद है जो आज की वास्तविकता को दर्शाती है। बैंकों के बाहर मुद्रा विनिमय या जमा के लिए और एटीएम के बाहर नकद निकासी के लिए लोगों की लंबी कतारें विमुद्रीकरण के लिए लग गई लेकिन निश्चित रूप से यह परेशानी थोड़े समय के लिए ही थी, परन्तु इसका फायदा यह हुआ की जयादातर लोग डिजिटल तरीके से लेन देन करने लगे।

विमुद्रीकरण नीति से कई उद्योगों को लाभ हुआ है और कुछ को क्षणिक नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के पास पैसे की कमी के कारण, विमुद्रीकरण के बाद की पहली तिमाई में मांग 30% –40% कम हो गई थी लेकिन समय बढ़ने के साथ ही यह प्रभाव कम हो गया और जैसे ही लोगों के हाथ में पर्याप्त नई मुद्रा आई, अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई।

बैंकों के कुल जमा निकासी पर विमुद्रीकरण का प्रभाव

- विमुद्रीकरण के कारण प्रचलन में मुद्रा में गिरावट के कारण बैंक जमा में वृद्धि हुई।
- संचलन में कुल मुद्रा में लगभग रु. 8,800 बिलियन (रु. 8.8 लाख करोड़) की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान एनआरआई जमाओं के बहिर्वाह के बाद भी बैंकिंग प्रणाली की कुल जमाराशियों में लगभग रु. 6,720 बिलियन (रु. 6.72 लाख करोड़) की तीव्र वृद्धि में परिलक्षित हुआ।
- दिसंबर 2016 के अंत और मार्च 2017 की शुरुआत के बीच प्रचलन में मुद्रा में लगभग रु. 2,600 बिलियन की शुद्ध वृद्धि हुई। इस दौरान बैंकों में ब्याज के रूप में आने वाली जमा राशि में भी मामूली गिरावट आई।
- 28 अक्टूबर, 2016 (नोटबंदी से पहले) और 17 फरवरी, 2017 (नवीनतम उपलब्ध) के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में रु. 5,549 बिलियन की वृद्धि हुई।

- एससीबी द्वारा जुटाई गई अधिकांश जमाराशियों को निम्नलिखित में लगाया गया है: (i) आरबीआई के पास विभिन्न अवधियों के रिवर्स रेपोय और (ii) बाजार स्थिरीकरण योजना (जो बैंकों की बैलेंस शीट में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का एक हिस्सा है) के तहत जारी नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी)।
- बैंकों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम में रूपये 1,008 बिलियन की वृद्धि हुई। अवधि के लिए वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात केवल 18.2 प्रतिशत था।
- वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त जमाराशियों को बड़े पैमाने पर तरल संपत्तियों में लगाया गया है। यह इस तरह के जमाराशियों के थोक की अपेक्षित क्षणभंगुर प्रकृति और कमजोर मांग के कारण हो सकता है जैसा कि क्रेडिट की धीमी वृद्धि में परिलक्षित होता है।

बैंकों की लाभप्रदता पर विमुद्रीकरण का प्रभाव

- बैंकों का शुद्ध लाभ अनिवार्य रूप से ऋणों और अग्रिमों और निवेशों पर अर्जित ब्याज और जमा और उधारों पर भुगतान किए गए ब्याज के बीच के अंतर को दर्शाता है, जिसे परिचालन लागत और प्रावधानों के लिए समायोजित किया गया है।
- ऋण और अग्रिम और निवेश, जो ब्याज आय के मुख्य स्रोत हैं, मिलकर 85 प्रतिशत से अधिक का गठन करते हैं (61 प्रतिशत ऋण और अग्रिम और 25 प्रतिशत निवेश द्वारा)।
- कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों की हिस्सेदारी में 4.1 प्रतिशत अंकों की तीव्र वृद्धि 39.3 प्रतिशत (17 फरवरी, 2017 तक) के परिणामस्वरूप कुल जमाराशियों की लागत में कमी आई है।
- बैंकों ने भी अपनी सावधि जमा दरों में कमी की है, नवंबर 2016—फरवरी 2017 के दौरान मध्य सावधि जमा दर में 38 बीपीएस की गिरावट आई।
- वित्त पोषण की लागत में गिरावट के परिणामस्वरूप धन आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत में नोटबंदी के बाद 70 बीपीएस तक की गिरावट आई है (नवंबर 2016—फरवरी 2017)।
- बैंकों ने रिवर्स रेपो और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत लगभग 6.23—6.33 प्रतिशत का रिटर्न अर्जित किया, जबकि सीएएसए जमा की लागत लगभग 3.2 प्रतिशत थी।
- तदनुसार, रिवर्स रेपो और एमएसएस प्रतिभूतियों के तहत एक तिमाही में लगभग रु. 6 ट्रिलियन की औसत तैनाती के लिए, विमुद्रीकरण के बाद बढ़ी हुई जमाराशियों से बैंकों की शुद्ध ब्याज आय लगभग रु. 45 बिलियन हुई है।
- बैंकों को कम लागत वाली कासा जमाराशियों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी का फायदा लेना जारी है, हालांकि प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि के साथ यह धीरे—धीरे कम हो रहा है।

- शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि को एसबीएन की निकासी और नए बैंक नोटों के इजेक्शन के प्रबंधन की लागत के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होगी (जैसे एटीएम मशीनों का अंशांकन, स्टाफ ओवरटाइम, सुरक्षा व्यवस्था, कम शुल्कधिजिटल मोड पर शुल्क की छूट) भुगतान), जिसका सटीक विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है।

साहित्य की समीक्षा

नितिन और शर्मिला (2016) ने विमुद्रीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अत्यकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसे प्रभाव तब हल हो जाते हैं जब नए मुद्रा नोट अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से प्रसारित होते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सरकार को विमुद्रीकरण के कारण उत्पन्न सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने में मदद करनी चाहिए।

निकिता गज्जर (2016) ने भारत में काला धन: वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां और विमुद्रीकरण पर एक अध्ययन पर विचार किया। उन्होंने रूपरेखा, नीतिगत विकल्पों और रणनीतियों का वर्णन किया, जिन्हें भारत सरकार को इस मुद्दे से निपटने और सरकार द्वारा सामना की जाने वाली भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाना चाहिए।

विजय और शिवा (2016) ने विमुद्रीकरण और इसके पूर्ण वित्तीय समावेशन की जांच की। उन्होंने महसूस किया कि विमुद्रीकरण के पुरस्कार बहुत उत्साहजनक हैं और विमुद्रीकरण देश के दीर्घकालिक हित में है। उन्होंने व्यक्त किया कि इसने अस्थायी दर्द दिया है लेकिन इसने वित्तीय सबक सिखाया है। इसने बैंकिंग उद्योगों को बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण पर काफी निवेश करने के लिए प्रभावित किया।

मनप्रीत कौर (2017) ने विमुद्रीकरण और कैशलेस भुगतान प्रणाली पर प्रभाव पर एक अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में कैशलेस प्रणाली से कम समय, कम लागत, कागज रहित लेन-देन आदि के कई उपयोगी लाभ हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी क्षेत्रों में भविष्य की लेनदेन प्रणाली कैशलेस लेनदेन प्रणाली है।

लोकेश उ.के. (2017) ने भारत में नोटबंदी और उसके प्रभावों पर शोध किया। उन्होंने भारत में नोटबंदी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित था। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन को खत्म करना और भ्रष्टाचार को कम करना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कुछ हद तक सफल हुई है। विमुद्रीकरण का भारतीय वित्तीय बाजारों पर छोटी अवधि के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि असली असर भविष्य में दिखेगा।

श्वेता सिंघल (2017) ने भारत में विमुद्रीकरण और ई-बैंकिंग पर शोध किया। यह ई-बैंकिंग सुविधाओं के बारे में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जागरूकता स्तर की जांच करने के लिए एक केस स्टडी थी और विमुद्रीकरण के बाद

यह कितना बढ़ा है। एनोवा परीक्षण के साथ 100 के एक नमूने के आकार का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया था कि ग्रामीण लोग शहरी लोगों से उनके जागरूकता स्तर के साथ—साथ ई—बैंकिंग के उपयोग स्तर में बहुत भिन्न हैं। यह पाया गया कि शहरी पुरुष युवाओं में ई—बैंकिंग के बारे में अधिक जागरूकता और उपयोग है। उन्होंने महसूस किया कि यह अध्ययन बैंकों को अपनी ई—बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी मददगार होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बैंकों के परिचालन पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. विमुद्रीकरण के बाद बैंक परिचालनों पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का पता लगाना।

अध्ययन की पद्धति— अध्ययन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें उपलब्ध प्रकाशित साहित्य जैसे किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और संबंधित सरकारी वेबसाइट शामिल हैं। यह अध्ययन सामान्य बैंकिंग परिचालनों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव की सीमा को देखने का प्रयास करता है।

विमुद्रीकरण और बैंक संचालन— विमुद्रीकरण ने उन चुनौतियों के अलावा ढेर सारी चुनौतियाँ ला दी हैं जिनका सामना बैंकों को पहले से ही करना पड़ रहा है। प्रभाव अत्यकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के थे। अत्यावधि में, इसने बैंकों को बाधित किया और बैंक संचालन करने के लिए दृढ़ता से जोर दिया और लंबे समय में इसने बैंकों को बिना किसी लागत के जमा को जमा करने में मदद की। यहां बैंकों पर विमुद्रीकरण के चार प्रभाव दिए गए हैं।

1. जमा राशि में वृद्धि: नोटबंदी से बैंकों में जमा राशि में वृद्धि हुई है। 500 रुपये और 1000 रुपये के रूप में बेहिसाब पैसा बैंकों में प्रवाहित हो रहा था जिसने जमा राशि का आकार बढ़ा दिया था। इसने बैंकों को जमा हथियाने और अपनी जमा राशि बढ़ाने में मदद की।

2. फंड की लागत में गिरावट: पिछले कुछ महीनों में डिपॉजिट में बढ़ोत्तरी हुई है। इसने बैंकों को जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा नकद जमा के रूप में रखने के लिए प्रेरित किया। पीएसयू बैंकों के पास डिपॉजिट का बड़ा हिस्सा (70% से अधिक) है और डिपॉजिट में वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ है, फंड की लागत में कमी होती है।

3. सरकारी बॉन्ड की मांग: विमुद्रीकरण के बाद जमा में तेज वृद्धि के बाद, बैंकों ने रिवर्स रेपो विकल्पों के तहत आरबीआई को ऐसी अतिरिक्त जमा राशि उधार देना शुरू कर दिया। पीएसयू बैंकों ने, विशेष रूप से, सरकारी बांडों में अतिरिक्त धन लगाया। बांड निवेश पर प्रतिफल से बैंकों की आय में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

4. ऋण देने में सुस्ती: नोटबंदी के बाद भी बैंकों की ऋण वृद्धि काफी कम है और सार्वजनिक जमा की राशि में वृद्धि हुई है। जिससे बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को कम करके जरूरतमंद समूह को पैसा उधार देने की कोशिश की है, लेकिन नोटबंदी के बाद कुछ महीनों में यह कम हुआ है।

विमुद्रीकरण के बाद बैंक परिचालनों पर परिणाम

नोटबंदी के बाद बैंक परिचालनों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। दोनों ने बैंकों की तरलता, लाभप्रदता और कर्मचारियों को प्रभावित किया है।

विमुद्रीकरण के सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं—

1. **जमा का मुक्त प्रवाह:** बैंकों ने विमुद्रीकरण के बाद काफी हद तक जमा राशि प्राप्त की है जिसे वे निवेश कर सकते हैं।
2. बैंकों की तरलता और लाभप्रदता में सुधार हुए हैं।
3. **बेहतर डिजिटल इंटरफ़ेस:** बैंक लेनदेन को निष्पादित करने के लिए डिजिटल उपकरणों और उपकरणों में सुधार से चोरी, डकैती और हेराफेरी जैसे विभिन्न कारणों से होने वाली नकदी हानि से बचा जा सका है।
4. **बैंक में लोगों का अधिशेष:** अधिशेष नकद एक निष्क्रिय संपत्ति है जो बैंक में रखे बिना कोई आय नहीं देती है। इसलिए, विमुद्रीकरण ने लोगों को किसी प्रकार की आय अर्जित करने के लिए अपने अधिशेष धन को बैंक में रखने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे लोगों को भी अधिशेष पर ब्याज का लाभ मिला।
5. **ग्राहकों की संख्या में वृद्धि:** विमुद्रीकरण ने जनता को बैंकों के साथ लेनदेन करने के लिए आने और निष्पादित करने के लिए प्रभावित किया है। इसने एक गैर आय वर्ग के लोगों को भी बैंक जाने और खाता रखने के लिए मजबूर कर दिया। इसने बैंकों में जमा कोष में वृद्धि करते हुए खाताधारकों की संख्या में वृद्धि की। इसी तरह, विमुद्रीकरण ने बैंकों के लिए कुछ परिचालनात्मक मुद्दे लाए हैं। इससे बैंक कर्मचारी परेशान हैं।

विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं—

1. **नकद आरक्षित आवश्यकता:** वृद्धिशील जमाओं पर 100: सीआरआर का मतलब है कि बैंकों ने रुपये पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया। लगभग एक पखवाड़े के लिए 3 लाख करोड़ जमा बैंकों पर रहा जिस पर बैंकों को कोई लाभ नहीं मिला।
2. **एटीएम शुल्क माफ किया गया:** प्रतिबंधित नोट एक्सचेंज के दौरान एटीएम शुल्क माफ कर दिया गया जिससे बैंकों को नुकसान हुआ।
3. **मर्चेट डिस्काउंट रेट से छूट:** बैंकों को प्रत्येक कार्ड लेनदेन का उपयोग करने पर व्यापारियों से 1% छूट शुल्क का नुकसान उठाना पड़ा।
4. **एसएमई की बिक्री में कमी और एनपीए पर प्रभाव:** विमुद्रीकरण के दौरान, कुछ एसएमई व्यवसायों ने अपनी बिक्री में 50–80 प्रतिशत की गिरावट देखी थी और वे बैंकों को देने वाली अपनी किश्तों में चूक कर सकते थे। जिसे बैंकों ने एनपीए मान लिया और बैंकों में इसका स्तर प्रभावित हुआ।
5. **कर्मचारियों पर तनाव:** बैंक कर्मचारियों पर दबाव और ओवरटाइम काम का माहौल था। इसने उन्हें उदास कर दिया और असंतुलित जीवन शैली को बनाए रखा।

निष्कर्ष

विमुद्रीकरण केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। इसी तरह, इसने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और परिवर्तन लाया। बैंक विमुद्रीकरण से प्रभावित प्रमुख संस्थान हैं। प्रतिबंधित मूल्यवर्ग को वापस गिरवी रखा गया और नागरिकों को बैंकों के साथ विनिमय करने की अनुमति दी गई। आदान-प्रदान करते समय, यह अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए परेशान हो गया और इसके नियमित खाते का संचालन प्रभावित हुआ। हालाँकि इसने बैंक के संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन इसने अर्थव्यवस्था को बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से देश के विकास को बढ़ाने में मदद की। नोटबंदी नवंबर 2016 में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा मुद्रा नोटों की जालसाजी को रोकने के प्रयास के साथ-साथ देश में काले धन पर कार्रवाई के लिए की गई थी। विमुद्रीकरण एक पीढ़ी का यादगार अनुभव है और यह हमारे समय की आर्थिक घटनाओं में से एक रहा है। इसका असर हर भारतीय नागरिक महसूस कर रहा है। विमुद्रीकरण तरलता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। काफी हद तक अधोषित आय (काला धन) बैंकों में जमा हुआ जिससे देश के राजस्व में वृद्धि हुई। फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण समेत सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिये उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया था। नोटबंदी के निर्णय ने देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली के औपचारिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः कुल मिलाकर नोटबंदी का बैंकों पर एवं देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

संदर्भ

1. Nithin Kumar A and Sharmila (2016). Demonetization and Its Impact on Indian Economy. International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Science. ISSN (P):2348-0521. ISSN (E): 2454-4728. Vol. 4. Issue12, Dec 2016. Pp 23-26.
2. Dr. Pratap Singh and Virender Singh (2016). Impact of Demonetization on Indian Economy. International Journal of Science Technology and Management. ISSN (O) 2394-1537. ISSN (P) 2394-1529. Vol. No.5, Issue No. 12, December 2016.
3. S Vijay Kumar and T Shiva Kumar (2016). Demonetization and Complete Financial Inclusion. International Journal of Management Research & Review. ISSN: 2249-7196. Volume 6. Issue 12.
4. Nikita Gajjar (2016). Black Money in India: Present Status and Future Challenges and Demonetization. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. ISSN:2321-7782. Volume 4, Issue 12, December 2016.
5. Office of the Development Commissioner (2016). Demonetization and Promoting use of digital payment system.
6. Economic Consequences of demonetization of Rs. 500 and Rs. 1000 notes. (2016). Care Ratings: Professional Risk Opinion.
7. Lokesh Uke (2017). Demonetization and its effects in India. SSRG International Journal of Economics and Management Studies. Volume 4. Issue 2. February 2017.

8. Dr. Sweta Singhal (2017). Demonetization and E-Banking in India. International Journal of New Technology and Research (IJNTR). ISSN: 2454-4116. Volume3. Issue1. January 2017. Pp 20-25.
9. Manpreet Kaur (2017). Demonetization: Impact on Cashless payment system. International Conference on Recent Trends in Engineering, Science and Management. ISBN:978-93-86171-21-4. 8th January, 2017.
10. <https://taxguru.in/rbi/demonetization-effect-banking-sector.html>
11. <http://bankersclub.in/impact-demonetization-banks/>